POSTAL REG. NO. JAIPURCITY/410/2021-23 (RNI.REG.NO 39658/1983) #ग्रा.ग./2022/अंक 04

मासिक प्रेषण दि. 8 अप्रेल, सी.एस.ओ., आरएमएस गाँधी नगर, जयपुर-15

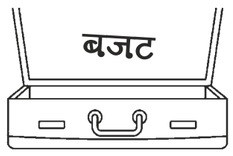

ग्राम गदर

वर्ष 1983 से प्रकाशित

प्रकाशन की तिथि : 01 अप्रेल, 2022 मूल्य 50 पैसे

आपके नाम चिट्ठी

जयपुर से जोग लिखी प्रदीप महता का सबको राम-राम/सलाम!

राज्य विधानसभा में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वित्त मंत्री के रूप में वित्तीय वर्ष 2022-23 का बजट रखा। बजट में खेती-किसानी को लाभदायक बनाने, स्वास्थ्य सुविधाओं को शतप्रतिशत निःशुल्क करने, शिक्षा की नींव को मजबूती देने, कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन स्कीम लागू कर लाभान्वित करने और महिलाओं को इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ स्मार्ट फोन मुफ्त देने जैसी कई बड़ी घोषणाएं कर सभी को खुश करने का प्रयास किया गया है।

अभी राजस्थान में बेरोजगारी दर सर्वाधिक है। ऐसे समय में रोजगार और आय सृजन के अवसर बढ़ाने से बड़ी कोई प्राथमिकता नहीं होनी चाहिए। राज्य सरकार को एक कदम आगे बढ़कर रोजगार सम्बंधित प्रोत्साहन योजनाएं लागू करनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने रिफाईनरी के पास पेट्रोलियम सह-उत्पाद आधारित जो खाका तैयार किया है और नए औद्योगिक क्षेत्रों की घोषणा की है। यह सराहनीय कदम है। इसके अलावा भी सरकार को प्रदेश की आर्थिक व्यवस्था को मजबूती देने के लिए कई नीतिगत कदम और उठाने होंगे।

मेरा मानना रहा है कि प्रदेश में राजस्व बढ़ाने, बजट घाटे को कम करने और वित्तीय अनुशासन अपनाने के लिए प्रशासनिक सुधारों के साथ-साथ नौकरशाही को अधिक सक्रिय और जवाबदेह बनाना बेहद जरूरी है। जितना वित्तीय संसाधनों को समय पर जुटाना जरूरी है, उतना ही जरूरी यह भी है कि उन्हें दक्षता के साथ निर्धारित समय पर योजनाबद्ध तरीके से खर्च किया जाए। जनता का पैसा जो राजकोष में आता है वह बेवजह खर्च नहीं हो, यह सुशासन का मूल मंत्र होना चाहिए।

देश की प्रगति का आधार: कृषि क्षेत्र का विकास

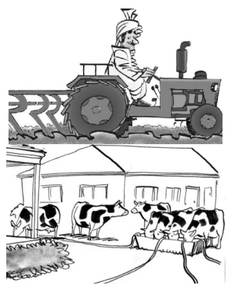

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पहली बार अलग से कृषि बजट पेश करते हुए कहा कि कृषि क्षेत्र देश की प्रगति का मुख्य आधार है। इसलिए बजट में खेती और किसानों को कई योजनाओं के जरिए प्रत्यक्ष रूप से फायदा पहुंचाने का प्रयास किया गया है। खासतौर पर मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना को 2 हजार करोड़ रुपए से बढ़ा कर 5 हजार करोड़ रुपए किया गया है। योजना को 11 मिशन के तहत पूरा किया जाना प्रस्तावित है।

बजट में किसानों को 20 हजार करोड़ रुपए का ब्याजमुक्त फसली ऋण वितरण का लक्ष्य रखा गया है। अकृषि क्षेत्र में 2000 करोड़ रुपए के ऋण वितरित कर एक लाख परिवारों को लाभान्वित किया जाएगा। प्रदेश में जैविक खेती को खास अहमियत देने के लिए 600 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। किसानों को सोलर पम्प के लिए 60 फीसदी अनुदान मिलेगा। 14 हजार 860 करोड़ रुपए विभिन्न सिचाई परियोजनाओं पर खर्च किए जाएंगे। सूक्ष्म सिचाई मिशन पर 2700 करोड़ रुपए खर्च होंगे।

प्रदेश में 18 नए कृषि महाविद्यालय खुलेंगे। बजट में सभी जिलों के किसानों को दिन में बिजली उपलब्ध कराने और सभी लम्बित कृषि विद्युत कनेक्शन दो साल में जारी करने का वायदा किया है। पशुपालकों का बीमा और 5 हजार नए डेयरी बूथ खोलने, दुग्ध उत्पादक संबल योजना में अनुदान दो रुपए प्रति लीटर को बढ़ाकर पांच रुपए किए जाने जैसी कई महत्वपूर्ण घोषणाएं बजट में हैं।

सबसे बड़ा कदम: सरकारी अस्पतालों में पूरा इलाज होगा मुफ्त

प्रदेश के बजट में स्वास्थ्य क्षेत्र को सर्वाधिक महत्व देते हुए सरकारी अस्पतालों में मिल रही निःशुल्क दवा व जांच योजना तथा चिरंजीवी बीमा योजना का दायरा बढ़ाया गया है। इससे अब आमजन को सरकारी ही नहीं बल्कि निजी क्षेत्र में भी निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिल सकेगा।

सरकारी अस्पतालों में सभी स्वास्थ्य सुविधाओं को शतप्रतिशत निःशुल्क कर, सरकार दवाओं और जांच योजनाओं की सुविधाओं का विस्तार करेगी। चिरंजीवी योजना के तहत 5 लाख रुपए की चिकित्सा बीमा राशि को बढ़ा कर 10 लाख रुपए कर दिया गया है।

अब तक इस योजना से लोगों ने 930 करोड़ रुपए का कैशलेस इलाज का लाभ उठाया है। इस योजना में 5 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा भी बीमित परिवारों को मिल सकेगा। प्रदेश में 15 खुलने वाले नए मेडिकल कॉलेजों के लिए 1,224 करोड़ रुपए के खर्च का प्रावधान बजट में प्रस्तावित है। प्रदेश के सभी जिलों में अब नर्सिंग कॉलेज होंगे। इससे मेडिकल शिक्षा और ज्यादा मजबूत हो सकेगी।

एक हजार नए उप स्वास्थ्य केंद्र खोले जाने और 100 से भी ज्यादा छोटे अस्पतालों को क्रमोन्नत किए जाने का प्रस्ताव बजट में किया गया है। जोधपुर में नया डेंटल कॉलेज शुरू किया जाएगा। आयुष सुविधा से वंचित 19 ब्लॉकों में 20 करोड़ की लागत से आयुष अस्पताल खोले जाना प्रस्तावित है।

विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस

प्रौद्योगिकी के साथ निष्पक्ष वित्तीय सेवाएं आवश्यक

"प्रोद्योगिकी के तेजी से विकास के साथ-साथ डिजिटल वित्तीय सेवाएं बढ़ी हैं। उपभोक्ता इसका उपयोग भी करने लगा है। इसका बहुत अधिक उपयोग उपभोक्ताओं ने नोटबंदी एवं कोरोना महामारी के दौरान किया है। लेकिन डिजिटल वित्तीय सेवाओं से बहुत अधिक मात्रा में किसी न किसी रूप में धोखाधड़ी के शिकार हुए हैं। प्रौद्योगिकी के बढ़ते प्रभाव के साथ निष्पक्ष डिजिटल सेवाएं होना आवश्यक है। सभी रेगुलेटर्स को चाहिए कि इस तरह की प्रणाली विकसित की जाए जिससे कि आम व्यक्ति इसका लाभ बहुत आसान तरीके से प्राप्त कर सकें।"

उक्त विचार 'कट्स' द्वारा विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस पर आयोजित 'निष्पक्ष डिजिटल वित्तीय सेवाएं' विषयक परिचर्चा में प्रदीप महता, महामंत्री 'कट्स' ने व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि डिजिटल वित्तीय सेवाओं में निजी डाटा खोने का डर रहता है तथा कई बार उपभोक्ता साइबर अपराध के शिकार हो जाते हैं।

परिचर्चा के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व रीजनल डाइरेक्टर मुनीष पी. कोठारी ने कहा कि डिजिटल युग में उपभोक्ताओं को लाभ तो मिला है लेकिन इसका सरलीकरण नहीं हो पाया है। कई ऐसे उपभोक्ता भी हैं जो डिजिटल वित्तीय सेवाओं से अनभिज्ञ होते हैं। उन्होंने कहा कि स्वयं सेवी संस्थाओं और वित्तीय सलाहकारों को उपभोक्ताओं में डिजिटल वित्तीय सेवाओं के प्रति जानकारी एवं जागरूकता बढ़ाने का काम करना होगा।

कार्यक्रम में राजस्थान विश्वविद्यालय के विधि विभाग के सहायक प्रोफेसर मनोज मीणा, इंडिक एसोसिएट के अभिषेक कुमार, भारतीय रिजर्व बैंक जयपुर के एफ.आई.डी.डी.विभाग के राकेश चन्द्र शर्मा सहित कई अन्य वक्ताओं ने भी अपने विचार साझा किए। परिचर्चा के प्रारंभ में 'कट्स' के सहायक निदेशक दीपक सक्सेना ने सभी संभागियों का स्वागत किया और कार्यक्रम का संचालन किया।

मजबूत होगी शिक्षा की नींव

बजट पेश करते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि कोरोना काल में विद्यार्थियों को पढ़ाई-लिखाई का बड़ा नुकसान हुआ है। इसकी भरपाई के लिए स्कूली विद्यार्थियों के लिए तीन माह की अवधि के ब्रिज कोर्स चलाए जाएंगे। इसके लिए 75 करोड़ रुपए का प्रावधान बजट में किया गया है। शिक्षा में अंग्रेजी माध्यम के प्रति रुझान को देखते हुए अंग्रेजी माध्यम स्कूलों का दायरा बढ़ाया गया है।

ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में एक-एक हजार अंग्रेजी माध्यम स्कूल और शुरू किए जाएंगे। प्रदेश में अब 3200 सरकारी अंग्रेजी माध्यम स्कूल हो जाएंगे। इन स्कूलों के लिए 10 हजार शिक्षकों की नई भर्ती होगी। प्रदेश के सभी 3820 सैकंडरी स्कूलों को सीनियर सैकंडरी स्तर पर क्रमोन्नत किया जाएगा।

ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर प्राथमिक विद्यालयों को क्रमोन्नत कर उच्चप्राथमिक विद्यालय बनाया जाएगा तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों को भी अपग्रेड कर सीधे सीनियर सैकंडरी स्कूल स्तर पर लाया जाएगा। प्राथमिक शिक्षा के लिए बजट में 14,730 करोड़ रुपए का प्रावधान है।

स्कूलों में मिड-डे मील पर 1,450 करोड़ रुपए खर्च होंगे। अल्पसंख्यकों के मदरसों व छात्रावासों के लिए नए कक्षा कक्ष बनाने व भवन निर्माण के लिए भी बजट में अलग से प्रावधान किए गए हैं। बजट में बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के मकसद से 19 जिलों में 36 कन्या महाविद्यालय खोले जाने और 25 कन्या महाविद्यालयों में नए विषय और संकाय शुरू करने जैसी कई अन्य घोषणाएं भी की गई है।

संविदा कार्मिकों के हित में उठाए कदम

सरकार ने बजट में संविदा कार्मिकों के हितों के लिए विशेष कदम उठाए हैं। इसी कड़ी में हाल ही जनवरी 2022 में राजस्थान कॉन्ट्रेक्ट्यूल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स लागू किए हैं। पूर्व में कार्यरत संविदा कार्मिकों को इन नियमों के तहत लाया जाकर लाभान्वित किया जाएगा।

इसके साथ ही प्रदेश के विभिन्न विभागों में कार्यरत मानदेय कर्मचारियों जैसे कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, आशा सहयोगिनी, प्रेरक, मिड-डे-मील कुक कम हैल्पर, लांगरी, ग्राम रोजगार सहायक, शिक्षाकर्मी, पेराटीचर्स आदि, जिनके मानदेय में प्रतिवर्ष वृद्धि का प्रावधान नहीं है, उनके मानदेय में एक अप्रेल, 2022 से 20 प्रतिशत वृद्धि किए जाने की बजट में घोषणा की गई है।

उद्योग क्षेत्र से पनपेंगे रोजगार के अवसर

मुख्यमंत्री द्वारा बजट में उद्योग क्षेत्र को दी गई रियायतों से प्रदेश में औद्योगिक विकास को बल मिलेगा और उससे लाखों रोजगार के अवसर पनपेंगे। रिफाइनरी के पास ही पेट्रोलियम सह उत्पाद आधारित पेट्रोलियम, केमिकल्स एंड पेट्रो-केमिकल्स इन्वेस्टमेंट रीजन (पीसीपीआइआर) का खाका तैयार है। यह अब जमीन पर आएगा। 17 जिलों में 32 नए औद्योगिक क्षेत्रों की घोषणा की है। सरकार ने पहले चरण में वर्ष 2021-22 में औद्योगिक क्षेत्र विहीन उपखंडों पर 64 औद्योगिक क्षेत्रों की घोषणा की थी। इन पर काम चल रहा है। माना गया है कि 11,000 करोड़ रुपए का निवेश पेट्रोकेमिकल क्षेत्र में होगा। प्रदेश में उद्यमता बढ़ेगी और 1.40 लाख नए रोजगार पैदा होंगे।

पर्यटन क्षेत्र को कई तरह से राहत देते हुए इसे उद्योग का दर्जा दिया गया है। एक हजार करोड़ का पर्यटन विकास कोष बनाया जाने की बात भी बजट में है। बजट में औद्योगिक इकाइयों की सुरक्षा के लिए राजस्थान औद्योगिक सुरक्षा बल (आरआइएसएफ) गठित किए जाने की घोषणा भी की गई है। इसमें दो हजार नए सुरक्षा कर्मियों की भर्ती की जाएगी।

प्रदेश के 20 चयनित औद्योगिक क्षेत्रों में 150 करोड़ रुपए की लागत से विकास के कार्य कराए जाएंगे। उद्योग प्रोत्साहन योजना में नए उद्योगों की स्थापना व विस्तार में ब्याज सब्सिडी की दर 8 फीसदी से बढ़ाकर अब 9 फीसदी की गई है। इससे सूक्ष्म, लघु और मध्यम औद्योगिक इकाइयों को लाभ मिलेगा।

कर्मचारी खुश: पुरानी पेंशन स्कीम लागू

बजट में पुरानी पेंशन स्कीम को लागू करने की घोषणा की गई है। इससे प्रदेश में 2004 के बाद लगे करीब 5 लाख शिक्षकों व कर्मचारियों को फायदा होगा। कर्मचारी पिछले कई सालों से नई पेंशन स्कीम को खत्म कर पुरानी पेंशन स्कीम को वापस लागू करने की मांग कर रहे थे।

पुरानी पेंशन स्कीम के लागू होने से महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी व ग्रेच्युटी का लाभ भी मिलेगा। रिटायरमेंट पर आधा वेतन मिलेगा। रिटायरमेंट के बाद मौत होने पर आश्रित को भी पेंशन मिलेगी। नई पेंशन स्कीम में वेतन से जो 10 फीसदी की कटौती हो रही थी वह बंद हो जाएगी।

बुनियादी ढांचे के विकास का खाका

प्रदेश में बुनियादी ढांचे को तीव्र गति देने के मकसद से बजट में ग्रामीण व शहरी विकास, बिजली, पानी और सड़क जैसे कई क्षेत्रों में तेजी से आगे बढ़ने का खाका तैयार किया गया है। केंद्र की तरह राज्य में भी स्मार्ट सुविधाएं विकसित करने का सपना संजोया गया है।

बजट में 25,260 करोड़ रुपए का प्रावधान ऊर्जा क्षेत्र के विकास के लिए निर्धारित है। विद्युत वितरण ढांचे को मजबूत करने पर 3,500 करोड़ रुपए खर्च होंगे। बजट घोषणा के अनुसार पचास यूनिट तक उपभोग करने वाले घरेलू उपभोक्ताओं को बिजली फ्री मिलेगी। अन्य उपभोक्ताओं को भी बिल में 175 रुपए से 750 रुपए तक सब्सिडी मिलेगी। इसमें 300 यूनिट से ज्यादा उपभोग करने वाले उपभोक्ता भी शामिल हैं, जिन्हें स्लेब के अनुसार छूट दी जाएगी।

हर घर नल से शुद्ध पेयजल पहुंचाने की मुहिम पर 60,600 करोड़ रुपए खर्च होंगे। कई बड़ी जल प्रदाय परियोजनाओं की सौगात भी है। कई बड़े बांध बनेंगे जिससे पेयजल व सिचाई के लिए पानी मिलेगा। प्रदेश की 24 पेयजल परियोजनाओं पर 13,921 करोड़ रुपए के काम होंगे।

प्रदेश के 4 हजार किलो मीटर राजमार्ग पर 1,200 करोड़ रुपए खर्च करने का प्रावधान बजट में है। एक हजार किलोमीटर लम्बाई के राजमार्गो को पहले चरण में 2 लेन किया जाएगा। प्रत्येक जिले की महत्वपूर्ण तीन क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत व उन्नयन पर 3,133 करोड़ रुपए खर्च करने का प्रावधान है तथा प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र की सड़कों के काम पर 10 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए जाने सहित कई योजनाएं है।

महिलाओं को मिलेगा घर बैठे लाभ

अब महिलाएं घर से ही काम कर आजीविका में योगदान दे सकेंगी इसके लिए राज्य सरकार ने बजट में जॉब वर्क योजना की शुरुआत करने की घोषणा की है। इस योजना के तहत 20 हजार महिलाओं को लाभान्वित किया जाएगा। इस योजना के लिए बजट में करीब 100 करोड़ रुपए का प्रावधान है।

इसके अलावा मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना में 1.33 करोड़ चिरंजीवी परिवारों की महिला मुखिया को तीन वर्ष की इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ स्मार्ट फोन मुफ्त देने की घोषणा भी बजट में की गई है। इस पर करीब 2,500 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष खर्चा आएगा। इससे सभी प्रकार की सेवाएं प्राप्त हो सकेंगी और शिकायतों का निवारण किया जा सकेगा।

इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना के तहत अब दूसरी संतान के जन्म पर छह हजार रुपए की सहायता अब पूरे प्रदेश में लागू की गई है। इससे 3 लाख 38 हजार गर्भवती महिलाएं लाभान्वित होंगी। पहले यह सहायता केवल प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर और बारां जिलों में ही दी जा रही थीं।

बढ़ाई एससी-एसटी विकास कोष राशि

बजट के इसी सत्र में राजस्थान स्टेट एससी एंड एसटी डवलपमेंट फंड बिल लाने की घोषणा की गई है। साथ ही एससी-एसटी विकास कोष की राशि को बढ़ाकर 500-500 करोड़ रुपए कर दिया गया है। इसमें से 200 करोड़ रुपए रोजगारोन्मुखी गतिविधियों एवं कृषि, 150 करोड़ रुपए शिक्षा व सामाजिक सुरक्षा एवं 150 करोड़ रुपए आधारभूत संरचना के लिए प्रस्तावित है।

सम्पादक, प्रकाशक एवं मुद्रक स्वत्वाधिकारी प्रदीप एस महता के लिए भालोटिया प्रिन्टर्स, जयपुर से प्रकाशित।

'अक्षत टावर', डी-217, भास्कर मार्ग, बनीपार्क, जयपुर 302016 फोनः 228 2821 से 23 फैक्सः 0141-228 2485

कम्पोजिंग एवं लेआउट राजकुमार त्रिवेदी, 'कट्स' जयपुर